तिब्बत देश

जनसंख्या – उपनिवेशवाद का चीनी हथियार

तीन महीने पहले चीन सरकार के निमंत्रण पर तिब्बत और चीन की यात्रा के बाद लौटे दो भारतीय विशेषज्ञों के साथ मेरी अलग–अलग हुई संक्षिप्त बातचीत ने मुझे बहुत बुरी तरह चौंकाया। इनमें से एक श्री विक्रम सूद हैं जो भारत की खुफिया एजेंसी 'रॉ' के प्रधान रह चुके हैं और दूसरे श्री मोहन गुरुस्वामी हैं जो कूटनीति और रक्षा मामलों के एक शोध केंद्र के प्रधान हैं। इस यात्रा में उनके साथ अंग्रेज़ी अखबार 'द हिंदू' के मालिक–संपादक कामरेड एन. राम भी थे जिनकी प्रसिद्धि पत्रकारिता के लिए तो जितनी भी हो पर चीन सरकार के प्रचार सहयोगी के रूप में अच्छी खासी है। कामरेड एन. राम ऐसे अकेले 'भाग्यशाली' भारतीय पत्रकार हैं जो चीन सरकार के खूब चहेते हैं। इतने कि शायद इसी कारण से चीन सरकार उन्हें बार–बार ऐसे महत्वपूर्ण भारतीय मेहमानों के साथ तिब्बत यात्रा पर भेजती है जो भारत में तिब्बत के सवाल पर जनता और सरकार पर असर जमाने की हैसियत रखते हैं।

अपनी इस तिब्बत यात्रा के बारे में उपरोक्त दोनों विद्वानों की पहली टिप्पणी यह थी कि दलाई लामा और उनके समर्थकों का यह प्रचार गलत है कि तिब्बत में चीन सरकार भारी संख्या में चीनी नागरिकों को बसा रही है। उनका कहना था कि ल्हासा में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे यह लगे कि वहां चीन ने भारी संख्या में चीनी नागरिकों को लाकर बसा दिया है। दोनों की राय थी कि ल्हासा में चीन ने जितने बड़े पैमाने पर विकास और निर्माण किया है उससे वहां तिब्बती नागरिकों को नई समृद्धि का जोरदार का लाभ मिल रहा है।

जब इन दोनों विद्वानों ने वहां के शानदार मॉल, बिल्डिंगों और बाजारों में तिब्बतियों की खुशहाली की बात की तो आखिर मुझे उनसे यह सवाल पूछना ही पड़ा कि क्या वे तिब्बती और चीनी चेहरों के अंतर को आसानी से समझ लेते हैं? मैं इसे इन दोनों का बड़प्पन ही कहूंगा कि दोनों ने अपनी–अपनी बातचीत में खुले मन से कबूल किया कि वे तिब्बती और चीनी चेहरों के बीच अंतर नहीं कर सकते। तब कहीं जाकर समझ में आया कि वे ल्हासा में बसाए गए चीनियों की समृद्धि को स्थानीय तिब्बतियों की तरक्की समझ कर चीनी विकास की तारीफ क्यों कर रहे थे। पर इसके साथ यह बात भी समझ में आयी कि तिब्बत पर चीन का प्रोपेगेंडा कितने असरदार तरीके से काम कर रहा है।

संयोग से इन दोनों की यह पहली तिब्बत यात्रा थी और मेहमान नवाज़ी चीन सरकार की थी। हाल के वर्षों में एक टूरिस्ट के तौर पर दो बार तिब्बत की निजी लंबी यात्राओं में जिस बात ने मुझे विचलित किया वह यह थी कि ल्हासा और शिगात्से जैसे शहरों में तिब्बतियों के मुकाबले चीनी नागरिकों की संख्या पांच से दस गुणा हो चुकी है जबकि चीनी प्रचार तंत्र इस अनुपात को 'बराबर' कहता आ रहा है। इन यात्राओं के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि वहां जितना भी विकास हो रहा है वह वहां बसाए जा रहे चीनी नागरिकों को स्थायी रूप से वहीं जमाने की नजर से और तिब्बत पर चीन का उपनिवेशवादी शिकंजा कसने की नीति के तहत किया जा रहा है। वहां के मूल तिब्बती नागरिकों को इस सारे विकास से केवल उतना ही लाभ मिल रहा है जो किसी महाभोज की बची जूठन से वहां के भिखारियों को मिलता है।

इन भारतीय विद्वानों के साथ तीन महीने पहले हुई इस निजी बातचीत का मैं शायद इस तरह सार्वजनिक हवाला न देता अगर चीन सरकार के प्रचार तंत्र से आने वाली कुछ ताज़ा खबरों ने चीनी झूठ को नंगा न कर दिया होता। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में चलने वाली सरकारी न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ की एक ताज़ा खबर के मुताबिक ल्हासा शहर की बढ़ती जनसंख्या को खपाने के लिए लिए शहर का विस्तार किया जा रहा है। ल्हासा के दक्षिणी हिस्से में क्यीचू नदी के किनारे 42 वर्ग किलोमीटर के नए क्षेत्र का विकास करके 1 लाख 40 हजार लोगों के लिए नए आवास बनाए जाएंगे। ल्हासा जिले के प्रमुख शी वेनचियांग ने कहा है कि यह विस्तार कार्य 2009 तक पूरा कर लिया जाएगा। एजेंसी के अनुसार ल्हासा की मौजूदा आबादी लगभग 6 लाख है जिसका 80 प्रतिशत हिस्सा पुराने शहर में रह रहा है जिसका क्षेत्रफल 59 वर्गकिमी है। सिनहुआ की एक और खबर के मुताबिक कभी 20 हजार आबादी वाले शहर में इन दिनों 70 हजार वाहन रजिस्टर्ड हैं। कारों की भारी संख्या की वजह से अब वहां भूमिगत पार्किंग बनायी गयी है। अपवादों को छोड़ ये सभी कारें और टैक्सियां वहां बसे चीनियों की हैं।

ल्हासा प्रशासन की यह घोषणा भले ही शहर के विकास के बारे में उसकी आधुनिक सोच को दिखाती है पर इसने चीन सरकार के इस झूठ से भी परदा उठा दिया है कि तिब्बत पर अपना उपनिवेशवादी नियंत्रण बढ़ाने के लिए वह चीन से लाकर चीनी नागरिकों को वहां बसा रही है। 1952 में चीनी नेता माओ ने एक घोषणा में अपनी चीन नीति स्पष्ट करते हुए कहा था, ''तिब्बत का क्षेत्रफल विशाल है पर आबादी बहुत कम है। इसे आज की 20–30 लाख आबादी से बढ़ाकर 50–60 लाख और फिर एक करोड़ से ऊपर ले जाना होगा।'' उसी दौर में तिब्बत के तीन में से दो प्रांतों आम्दो और खम को आसपास के चीनी प्रांतों सिचुआन, युन्नान, गांसू और चिंघाई में मिलाकर बाकी बचे हिस्से को 'टिबेट आटोनामस रिजन' यानी 'टार' नाम दे दिया गया था। 1985 में नई दिल्ली में चीनी दूतावास की ओर से जारी एक दस्तावेज़ में कहा गया था कि तिब्बत, सिंकियांग और भीतरी मंगोलिया की कम आबादी को देखते हुए वहां अगले 30 साल में नए चीनी नागरिकों को बसाकर वहां की आबादी को 6 करोड़ करने की जरूरत है। मगर बाद में अंतर्राष्ट्रीय विरोध को देखते हुए चीन सरकार ने वहां चीनी नागरिकों को बसाने की नीति को छिपाना शुरू कर दिया।

मार्च 1959 में जब तिब्बती जनता ने विदेशी चीनी सेना के खिलाफ ल्हासा में आंदोलन चलाया उस समय पूरे तिब्बत की आबादी केवल 60 लाख थी। तब ल्हासा शहर की अपनी आबादी लगभग 20 हजार थी जो वार्षिक मोनलम समारोह के तीर्थयात्रियों के कारण उन दिनों लगभग एक लाख तक पहुंची हुई थी। उसके बाद के दो दशक में चीनी नीतियों की वजह से तिब्बत के 12 लाख से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। इस सबके बावजूद अब ल्हासा की जनसंख्या का 6 लाख होना यही दिखाता है कि वहां चीनी नागरिकों को लाकर बसाने का अभियान जारी है। 12 मई 1993 को सिचुआन में हुई 'बैठक नंबर 512' में चीन सरकार ने तय किया था कि तिब्बत में चीन विरोध को हमेशा के लिए खत्म करने और तिब्बत समस्या का 'आखिरी समाधान' निकालने के लिए वहां चीनी नागरिकों को बसाया जाए ताकि तिब्बतियों को वैसे ही अर्थहीन अल्पसंख्यक बना दिया जाए जैसा भीतरी मंगोलिया और सिंकियांग में किया गया है।

2002 में 2000 की चीनी जनगणना के प्रकाशित आंकड़े प्रकाशित करते हुए चीन सरकार ने 'टार' की जनसंख्या 26 लाख, सिचुआन की 8 करोड़ 23 लाख, युन्नान की 4 करोड़ 24 लाख, चिंघाई की 48 लाख और गांसू की 2 करोड़ 51 लाख बतायी थी। यह दिखाता है कि खम और आम्दो के प्रांतों में तिब्बतियों की संख्या चीनी नागरिकों की विशाल संख्या के सामने अर्थहीन होकर रह गई है। और अब तिब्बत में चीनी रेलवे आने के बाद वहां चीनी नागरिकों को भारी संख्या में बसाने की सुविधा ने तिब्बत के अस्तित्व पर एक और गंभीर खतरा ला खड़ा किया है। तिब्बत में जनसंख्या को उपनिवेशवाद के हथियार की तरह इस्तेमाल करने की इस चीनी नीति ने भारत की सुरक्षा के लिए भी एक स्थायी और गंभीर खतरा खड़ा कर दिया है तथा दुनिया के सामने एक नैतिक चुनौती।

– विजय क्रान्ति

फोटो : विजय क्रान्ति

ल्हासा शहर का बदलता रूप : चीनी नागरिकों को बसाने के लिए

ल्हासा शहर में चीनी झूठ बेनकाब

जनसंख्या का विस्फोट, नई राजधानी बनाने का फैसला, ट्रैफिक जाम मगर बीजिंग का दावा कि चीनी नहीं बसाए

चीनी प्रशासन जिन लोगों को 'स्थानीय' बता रहा है उन चीनी नागरिकों को पिछले कुछ साल से तिब्बत लाकर बसाया जा चुका है। पचास साल पहले तक यहां की जनसंख्या सिर्फ 20,000 थी। अब यह 6 लाख से ऊपर है और चीनी मूल के लोगों की संख्या अधिक है।

ल्हासा 14 नवंबर, चीन सरकार बार बार दुनिया से यही कहती आ रही है कि वह तिब्बत में चीनी लोगों को नहीं भेज रही है। लेकिन चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की ताज़ा खबरों ने चीन के इस प्रोपेगेंडे की कलई खोल कर रख दी है। सिन्हुआ के एक समाचार में कहा गया है कि ल्हासा की बढ़ती जनसंख्या के लिए एक नया जिला जोड़कर नगर का विस्तार किया जा रहा है।

नया जिला लियूवू न्यू डिस्ट्रिक्ट ल्हासा की क्यूचू नदी के दक्षिणी किनारे पर मौजूदा पुराने शहर के सामने होगा। नया जिला 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगा जिसमें 1 लाख 10 हजार स्थानीय लोगों के लिये आवास होंगे। यह जानकारी जिला सरकार के प्रमुख शी वेनचियांग ने दी।

यह उल्लेखनीय है कि नया जिला ल्हासा रेलवे स्टेशन के आस पास ही स्थापित किया जा रहा है जो कि तिब्बत और चीन को जोड़ने वाली रेल प्रणाली का अंतिम सिरा है।

लियूवू जिले के 2009 तक पूरा होने की संभावना है। स्थानीय सरकार ने नये जिले में चार सड़कों के निर्माण का काम शुरू कर दिया है जिस पर 11.4 करोड़ युआन खर्च होंगे।

नये जिले को पुराने शहर से जोड़ने के लिये एक पुल होगा। इसके अलावा गोंगकार एयरपोर्ट के लिये एक हाइवे भी होगा। यह एयरपोर्ट तिब्बत में सबसे बड़ा है।

शी ने कहा,''नये जिले से पुराने शहर में प्राचीन भवनों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी जो कि गत दशक में जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण पैदा हुआ है।''

समुद्र तल से 3,600 मीटर उंचाई पर स्थित ल्हासा में सात काउंटी हैं और एक जिला है जिनका कुल क्षेत्रफल 30,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल जनसंख्या लगभग 6 लाख है जिसका 80 प्रतिशत हिस्सा पुराने शहर में बसता है जो मात्र 59 वर्ग किलोमीटर में है। ये सरकारी आंकड़े चीन सरकार के बार बार किये जाने वाले उस दावे को खारिज करते हैं कि चीन की ओर से तिब्बत में कोई नये लोग नहीं भेजे जा रहे हैं। चीन की बमबारी तथा गिरफ्तारी से बचने के लिये दलाई लामा मार्च 1959 ने भागकर भारत में शरण ली थी। उन दिनों शहर में चलने वाले मोनलम त्यौहार के लिए बाहर से आए हजारों तीर्थयात्रियों समेत ल्हासा की कुल जनसंख्या केवल 1 लाख थी। इसमें नगर की अपनी संख्या लगभग 20 हजार थी।

पिछले कई साल से चीन सरकार ने लाखों चीनी नागरिकों को चीन से लाकर तिब्बत में बसाने का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत ल्हासा और शिगात्से जैसे मुख्य शहरों में भारी पैमाने पर निर्माण और विकास कार्य किए गए हैं जिनका लक्ष्य अधिक से अधिक चीनी नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें वहां स्थायी रूप से बसने को प्रेरित करना है। रेलवे के आने के बाद चीनी जनसंख्या को बुलाने और यहां बसाने का काम नई गति पकड़ चुका है।

लगभग 1,300 साल पुरानी इस क्षेत्रीय राजधानी में तिब्बत बौद्धमत से जुड़ी अनेक धरोहरे हैं। इनमें सबसे प्रमुख पोताला पैलेस है जिसे यूनेस्को ने 1994 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया था।

शी ने कहा,''तिब्बत के आर्थिक, विशेषकर पर्यटन क्षेत्र में विकास के साथ और अधिक लोग ल्हासा में रहने का फैसला कर रहे हैं जिससे पुराना जिला विकास आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता।''

अधिकारियों के अनुसार स्थानीय सरकार नये जिले का विकास तिब्बत के एक हाई टेक औद्योगिक एवं बिजनेस सेंटर के रूप में करना चाहती है। इससे स्थानीय लोगों को 1,14,000 रोजगार मिलेंगे। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि चीनी प्रशासन जिन लोगों को 'स्थानीय' बताकर उनके लिए नए रोजगार विकसित कर रहा है। इन चीनी नागरिकों को पिछले कुछ साल से तिब्बत लाकर बसाया जा चुका है।

उन्होंने कहा,''तिब्बत की 17 प्रमुख कंपनियों ने अपने संयंत्र तथा मुख्यालय नये जिले में स्थानांतरित करने का फैसला किया है जिस पर 82 करोड़ युआन का निवेश होगा।''

तिब्बत में पर्यटन बढ़ रहा है

सिन्हुआ की 12 नवंबर की एक अन्य खबर के अनुसार इस साल के पहले दस माह में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 37.2 लाख पर्यटक आये और यह संख्या गत साल की तुलना में काफी अधिक है। पर्यटकों के आगमन से इस इस क्षेत्र को 4.4 अरब युआन यानी लगभग 55 करोड़ अमेरिकी डालर मिले हैं। गत वर्ष 25 लाख पर्यटक आये थे और इससे 34 करोड़ 60 लाख अमेरिकी डालर की कुल आय हुई थी। जो पूरे टार–तिब्बत क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद, का 9.6 प्रतिशत है।

उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल 40 लाख पर्यटक इस क्षेत्र में आयेंगे और तिब्बत की जीडीपी में इस क्षेत्र का हिस्सा 12 प्रतिशत होगा।

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र 'टार' की सरकार के उपाध्यक्ष वू यिंगचई ने रूस की संवाद समिति आरआईए के तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को एक साक्षात्कार में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ''इस क्षेत्र को लेकर विदेशों में काफी जिज्ञासा है। दस में से हर एक पर्यटक विदेशी होता है।''

क्षेत्रीय विकास एवं सुधार आयोग के उपाध्यक्ष ही बेनयुन का कहना है कि पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी का बहुत सा श्रेय चिंघाई–ल्हासा रेलवे को जाता है जो एक जुलाई 2006 को शुरू हुई।

सिन्हुआ के आमंत्रण पर आरआईए के प्रेस प्रतिनिधि ा मंडल ने नवंबर माह में बीजिंग तथा तिब्बत का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य विकास, आर्थिक निर्माण तथा धर्म आदि के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना था।

ट्रैफिक जाम और कारों की बाढ़

बीजिंग एसोसिएटिड प्रेस एजेंसी के अनुसार तिब्बत की राजधानी ल्हासा में कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे वहां ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर हो गई और अधिकारियों को पहली भूमिगत कार पार्किंग खोलनी पड़ी है।

सरकारी संवाद समिति सिन्हुआ ने यह जानकारी दी। इसने कहा है कि ल्हासा में 4,00,000 लोग हैं और 70 हजार पंजीकृत वाहन हैं। प्रति व्यक्ति कार स्वामित्व के हिसाब से ल्हासा और बीजिंग की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं है।

फोटो : विजय क्रान्ति

ल्हासा शहर में कूड़ा बीनते तिब्बती बच्चे : उपनिवेशवाद का प्रसाद

चीन से आ रहे अनाप शनाप धन ने ल्हासा की स्थिति को बदल कर रख दिया है। पचास साल पहले तक यहां की जनसंख्या सिर्फ 20,000 थी। इस शहर को तिब्बती संस्कृति का प्रतीक माना जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब यह आधुनिक ढांचे का अस्त व्यस्त शहर होता जा रहा है जहां चीनी मूल के लोगों की संख्या अधिक है।

ल्हासा में कारों की बढ़ती संख्या इसके आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने का नवीनतम संकेत है। चीन के बीजिंग आदि शहर तो पहले ही यातायात जाम की भारी समस्या से दो चार हो रहे हैं। चीन सरकार का मानना है कि तिब्बत में पैसा लगाकर वह तिब्बत के संसाधनों का दोहन आसानी से कर सकेगी।

चीन के सैनिक 1951 में इस क्षेत्र में आये थे और उन्होंने 1959 में मूल शासक दलाई लामा को पूरी तरह सत्ताहीन कर दिया। सेल फोन नेटवर्क, नई सड़कें तथा ल्हासा बीजिंग रेल मार्ग जैसी सुविधाओं के साथ इस क्षेत्र में चीनी मूल की जनसंख्या बढ़ रही है।

तिब्बतियों की चिंता यही है कि बढ़ती चीनी हान जनसंख्या आने वाले दिनों में तिब्बती बौद्ध चरित्र को पूरी तरह से ढंक लेगी।

चीन का दावा है कि तिब्बत हमेशा से ही उसका अंग रहा है जबकि अनेक तिब्बती कहते हैं कि उनके जीवन में ही तिब्बत एक अलग देश था। मूल तिब्बतियों को धर्म तथा समाज में चीनी सरकार के हस्तक्षेप पर गहरा असंतोष है।

वर्ष 1960 में चीन ने हजारों तिब्बती बौद्ध विहारों तथा मंदिरों को नष्ट कर दिया था। फिलहाल विहारों पर चीनी के कम्युनिस्ट अधिकारी निगरानी रखते हैं और यह नियंत्रण दिन प्रतिदिन कड़ा होता जा रहा है।

ल्हासा और शिगात्से जैसे मुख्य शहरों में भारी पैमाने पर निर्माण और विकास का लक्ष्य अधिक से अधिक चीनी नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें वहां स्थायी रूप से बसने को प्रेरित करना है। रेलवे के आने के बाद चीनी जनसंख्या को बुलाने और यहां बसाने का काम नई गति पकड़ चुका है।

तिब्बती शरणार्थियों को चीन भेजने के विरोधी और नेपाल पुलिस : अमानवीय मेजबानी

नेपाल ने 5000 तिब्बतियों को अमेरिका में शरण लेने से रोका

चीनी दबाव में नेपाल सरकार की घुटने टेक नीति

काठमांडो, 31 अक्तूबर चीन सरकार के दबाव में आकर नेपाल सरकार ने 5,000 तिब्बती शरणार्थियों को अमेरिका में शरण लेने से रोक दिया है। अमेरिका की जनसंख्या, शरणार्थी तथा आव्रजन मामलों संबंधी सहायक विदेश मंत्री सुश्री एलेन सोरब्रे ने यह रहस्योद्घाटन किया। वह नेपाल में रह रहे भूटानी शरणार्थियों के लिये यहां आई थीं।

फिलहाल नेपाल में लगभग 14,000 तिब्बती शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं जिन्होंने खुद को शरणार्थी के रूप में सरकारी तौर पर पंजीकृत कराया हुआ है।

चीन को इस बात की चिंता है कि अगर तिब्बती शरणार्थियों को अमेरिका में शरण मिली तो इससे तिब्बत से पलायन की घटनाएं बढ़ेंगी तथा तिब्बत में खराब हालात की ओर दुनिया का ध्यान भी जायेगा।

चीन सरकार के दबाव के कारण नेपाल सरकार ने इन शरणार्थियों पर कड़ा नियंत्रण लगाया हुआ है। यहां तक कि उन्हें अपने देश के निर्वासित शासक और धार्मिक नेता दलाई लामा के जन्म दिन जैसे सामान्य समारोह मनाने की भी अनुमति नहीं है।

नेपाल में तिब्बतियों को किसी तरह का संगठन पंजीबद्ध करने की अनुमति भी नहीं है। चीन तो मानता ही नहीं कि नेपाल में कोई तिब्बती शरणार्थी है। बल्कि उसका दावा है कि नेपाल में रहने वाले तिब्बती केवल गैरकानूनी आव्रजक हैं।

अमेरिकी अधिकारी ने नेपाल के कांतिपुर टेलीविजन चैनल को आज बताया कि शरणार्थियों को बसाने के कार्यक्रम के तहत अमेरिका ने गत वर्ष 5 हजार तिब्बती शरणार्थियों को अपने यहां शरण देने का प्रस्ताव किया था। लेकिन नेपाली सरकार ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया जिससे यह पेशकश बेकार गई। नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों को नेपाल से बाहर की यात्रा करने के लिये भी सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। नेपाल के साथ चीन के रिश्तों में तिब्बत बड़ा मुद्दा है। तिब्बत के सवाल पर चीन सरकार नेपाल सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखती है।

इस तरह नेपाल में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के चलते नेपाल सरकार ने दो साल पहले तिब्बत से भाग कर आए 16 तिब्बती शरणार्थियों को चीनी सेना के हाथ सौंप दिया था जिसकी विश्व स्तर पर आलोचना हुई थी। चीन को इस बात की चिंता है कि अगर तिब्बती शरणार्थियों को अमेरिका में शरण मिली तो इससे तिब्बत से पलायन की घटनाएं बढ़ेंगी तथा तिब्बत में खराब हालात की ओर दुनिया का ध्यान भी जायेगा। इसीलिये वह आजकल कोईराला सरकार पर दबाव बना रहा है कि तिब्बती शरणार्थियों को नेपाल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाये।

हर साल 2500 से 3500 तिब्बती चीनी जुल्मों से बचने के लिए तिब्बत से भागकर नेपाल के रास्ते भारत आते हैं। ये लोग बर्फीले पर्वतों के बीच दुर्गम रास्तों से होते हुए और जान जोखिम में डालकर नेपाल पहुंचते हैं और वहां से भारत में धर्मशाला चले जाते हैं जो दलाई लामा और निर्वासित तिब्बत सरकार का मुख्यालय है।

चीन यह दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि तिब्बती लोग उसके शासन में प्रसन्न एवं संतुष्ट हैं इसलिये वह नहीं चाहता कि लोग भागकर बाहर जाएं। इसी कारण उसने अपने सीमा रक्षक सैनिकों को भागने वाले निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का अधिकार भी दिया हुआ है। कुछ महीने पहले तिब्बत से भागते कुछ शरणार्थियों को चीनी सैनिकों ने गोलियों से मार डाला था। इस कांड को देख रहे एक यूरोपीय पर्वतारोही ने फिल्म पर उतार लिया था जिसे बाद में दुनिया भर के टीवी चैनलों पर दिखया गय और चीन की बदनामी हुई।

सुश्री सोरब्रे ने कांतिपुर टेलीविजन से कहा कि उनकी सरकार अपने प्रयासों को जारी रखेगी। काठमांडो में दलाई लामा के प्रतिनिधि कार्यालय को नरेश ज्ञानेंद्र ने अपने कार्यकाल में बंद करवा दिया था। बाद में एक एनजीओ कार्यालय खोलने की अनुमति दी लेकिन चीन के दबाव के आगे झुकते हुए कोइराला सरकार ने अनुमति वापस ले ली और कार्यालय को बंद करवा दिया। सत्ता में आने पर माओवादी नेता प्रचंड ने घोषणा की थी कि दलाई लामा कार्यालय को नेपाल में फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तिब्बती शरणार्थियों को चीन भेजने के विरोधी और नेपाल पुलिस : अमानवीय मेजबान

चीनी सेना से बौद्ध प्रतिमा बचाने के लिये तिब्बतियों का प्रदर्शन

सैनिकों ने गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा तोड़ी

आईटीसी 1 नवंबर, प्रत्यक्षदर्शियों से प्राप्त समाचारों के अनुसार माऊंट कैलाश के निकट दारछेन कस्बे में स्थानीय तिब्बतियों ने 28 सितंबर को गुरू रिंपोछे यानी गुरु पद्मसंभव की प्रतिमा को चीनी अधिकारियों द्वारा तोड़ने से बचाने के लिये जोरदार प्रदर्शन किया। गुरु पद्मसंभव पहले भारतीय बौद्ध गुरु थे जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का संदेश दिया था। लगभग 20 स्थानीय तिब्बती ग्रामीणों ने प्रतिमा को बचाने के लिए इस प्रतिमा के चारों और मानव श्रृंखला बनाई लेकिन सशस्त्र चीनी पुलिस दल ने उन्हें वहां से जबरन हटा दिया और दो मीटर ऊंची इस प्रतिमा को नष्ट कर दिया।

लेकिन तिब्बतियों के इस प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि अपनी धार्मिक आस्था के प्रतीकों को नष्ट करने के खिलाफ उनमें इतना रोष था कि उन्होंने इस प्रदर्शन के परिणामों की भी चिंता नहीं की। इस प्रतिमा को ढहाना इस बात का नया सुबूत है कि तिब्बत में धार्मिक आजादी को किस तरह से सीमित किया जा रहा है। चीन सरकार ने तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र 'टार' में धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए जनवरी 2007 से नये नियम लागू किये हैं। तब से लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं।

दारछेन में तिब्बतियों के प्रतिमा को बचाने के प्रयास के प्रत्यक्षदर्शी एक विदेशी पर्यटक ने इंटरनेशनल कैंपेन फार टिबेट को बताया, ''हमने यह अफवाह सुनी थी कि चीनी सशस्त्र सेना एक प्रतिमा को ध्वस्त करने जा रही है। हमारे ठहरने के स्थान से यह स्पष्ट दिख रहा था कि लगभग 20 लोगों का एक समूह गुरू रिंपोछे की इस प्रतिमा के आसपास मानव श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहा है। माहौल तनावपूर्ण था। बाद में एक तिब्बती महिला ने मुझे एक तरफ ले जाकर इस बारे में बताया। उसकी आंखों में आंसू थे और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने कहा कि चीनी अच्छे लोग नहीं हैं। वे प्रतिमा को तोड़ने जा रहे हैं। महिला ने मुझसे आग्रह किया कि मैं इस सबकी तस्वीरें लेकर दलाई लामा तक पहुंचाऊं।''

पश्चिम के इस पर्यटक ने बताया कि पुलिस ने बाद में उनके पर्यटक समूह को भी रोका और उन पर इस विरोध प्रदर्शन के चित्र लेने का आरोप लगाया। उन्होंने समूह के कैमरों की जांच की मांग की। समूह के पास इस कार्रवाई के फोटो नहीं थे केवल वह फोटो थी जिसमें प्रतिमा की जगह केवल उसका उसका टूटा हुआ आधार ही दिख रहा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले तिब्बत के सबसे पुराने विहार साम्ये में भी गुरू रिंपोछे की एक प्रतिमा को मई में ढहा दिया गया था।

पर्यटक शाम को जब लौटे तब तक तिब्बतियों को सेना ने वहां से हटा दिया था लेकिन लगभग 80–100 सशस्त सैनिक वहां मौजूद थे। एक अन्य पर्यटक ने बताया कि इन सैनिकों ने चार बजे के बाद धीरे धीरे प्रतिमा को पूरी तरह से ढहा दिया और वहां केवल उसका आधार बचा। इस बीच सादे कपड़ों वाले दो अधिकारियों ने पर्यटक समूह पर इस प्रकिया की फोटो लेने के आरोप भी लगाये। एक पर्यटक ने कहा ''तिब्बती बहुत निराश थे और माहौल तनावपूर्ण था।''

उल्लेखनीय है कि मई 2007 में अधिकारियों ने गुरू रिंपोछे की ही 30 फीट उंची प्रतिमा को मिटाने के आदेश दिये थे जिसपर सोने और तांबे की परत चढाई गई थी। यह प्रतिमा चीनी बौद्धों ने साम्ये विहार को भेंट की थी। चीन में तिब्बती बौद्धमत में भारी रुचि देखी जा रही है और अनेक चीनी नागरिक तिब्बती गुरुओं का उपदेश लेने और तीर्थयात्रा के लिए तिब्बत की यात्रा पर जाते हैं।

चीन की सरकार ने तिब्बत में बड़े आकार की प्रतिमाओं की स्थापना को नियंत्रित करने के लिये नये नियम लागू किये हैं। साम्ये विहार की लोकतांत्रिक प्रबधंन समिति ने एक अप्रत्याशित वक्तव्य में इस प्रतिमा को हटाये जाने की पुष्टि की थी। हालांकि इस वक्तव्य में कहा गया था कि यह प्रतिमा चीनी नियमों के अनुरूप नहीं दी इसलिये विहार ने इसे स्वयं ही हटा दिया।

लगभग 20 लोगों का एक समूह गुरू रिंपोछे की इस प्रतिमा के आसपास मानव श्रृंखला बनाने की कोशिश कर रहा है। माहौल तनावपूर्ण था। बाद में एक तिब्बती महिला ने मुझसे अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में आग्रह किया कि मैं इस सबकी तस्वीरें लेकर दलाई लामा तक पहुंचाऊं।

कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर द्वारा दलाई लामा का स्वागत : नैतिक साहस

कनाडा के प्रधानमंत्री पर चीन आग बबूला

चीनी विरोध के बावजूद स्टीफन हार्पर ने अपने सरकारी कार्यालय में दलाई लामा से औपचारिक मुलाकात की

तिब्बती नेता दलाई लामा के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की बैठक से चीनी प्रतिनिधि मंडल बेहद बौखला गया। वे इस हद तक बौखलाए हुए थे कि उन्होंने उक्त बैठक की तुलना क्यूबेक अलगावादियों से चीनी अधिकारियों की बैठक से कर डाली।

ओटावा, 30 अक्तूबर कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने चीन सरकार की चेतावनियों को किनारे करते हुए 29 अक्तूबर के दिन दलाई लामा के साथ अपने सरकारी कार्यालय में औपचारिक बातचीत की। इस तरह से वे कनाडा के पहले नेता बन गये हैं जिन्होंने अपनी पहल पर तिब्बत के निर्वासित शासक और धर्मगुरू दलाई लामा से सरकारी स्तर पर मिलने का फैसला किया।

बहुसंस्कृति मंत्री जेसन केनी ने इस बैठक के बारे में कहा ''स्पष्ट रूप से यह एक ऐतिहासिक बैठक थी।'' उन्होंने कहा,''मुझे उम्मीद है कि समूची दुनिया इस संदेश को समझेगी कि 72 वर्षीय बौद्ध भिक्षु पर हमला करने से कुछ हासिल नहीं होगा।'' उन्होंने कहा कि दलाई लामा तो महज अपने क्षेत्र के लोगों के लिये सांस्कृतिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।

केनी ने कहा कि दोनों नेताओं की बैठक हार्पर के कार्यालय में हुई और लगभग 40 मिनट तक चली इस बैठक में दोनों नेताओं ने खुलकर विचारों का आदान प्रदान किया।'

उन्होंने कहा कि बैठक में मानवाधिकार, तिब्बत के इतिहास तथा इसके लोगों के संकट पर विचार विमर्श किया गया। दलाई लामा ने उन्हें कनाडा की मानद नागरिकता देने के लिये हार्पर का धन्यवाद दिया।

केनी के अनुसार दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में नाटो के अभियान पर कोई चर्चा नहीं की। दलाई लामा इस बारे में पहले ही चिंता जता चुके थे।

इससे पहल चीन सरकार यह चेतावनी दे चुकी थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री या किसी वरिष्ठ सरकारी नेता द्वारा दलाई लामा की अगवानी का असर चीन–कनाडा संबंधों पर पड़ सकता है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर केनी ने इस चेतावनी को खारिज कर दिया।

चीन की तिलमिलाहट

ओटावा से प्रकाशित होने वाले दैनिक ग्लोब एंड मेल ने अपनी छह नवंबर की एक रिपोर्ट में कनाडा की यात्रा पर आए चीन के कुछ सरकारी तिब्बत विशेषज्ञों के बयानों का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बती नेता दलाई लामा के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की बैठक से चीनी प्रतिनिधि ा मंडल बेहद बौखला गया। वे इस हद तक बौखलाए हुए थे कि उन्होंने उक्त बैठक की तुलना क्यूबेक अलगावादियों से चीनी अधिकारियों की बैठक से कर डाली।

चाइना टिबेटोलाजी रिसर्च सेंटर के एक रिसर्चर एन केइडन ने इस बारे में कहा,' कल्पना करिये कि हमारी सरकार कनाडा से क्यूबेक को अलग करने का समर्थन करे तो आप कैसा महसूस करेंगे?'

हान चीनी एन उन चार तिब्बती विशेषज्ञों में शामिल हैं जो कनाडा की यात्रा पर आये थे। इनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य कनाडा में दलाई लामा को दिए गए शानदार सम्मान की आलोचना करना था।

चीन दूतावास में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एन ने कहा,''हम दोस्ती के लिये यहां आये हैं लेकिन कनाडा की सरकार ने जो किया वह किसी भी तरह दोस्ती के दायरे में नहीं आता है।'' उनका इशारा परम पावन दलाई लामा का ओटावा में जबरदस्त स्वागत की ओर था।

उन्होंने कहा कि चीनी जनता ने कनाडा के हीरो नार्मन बेथुन द्वारा कम्युनिस्ट क्रांति को दिया गया समर्थन याद है। लेकिन उसे श्री हार्पर द्वारा दलाई लामा के स्वागत से ठेस पहुंची है। दलाई लामा को कनाडा की मानद् नागरिकता से सम्मानित किया गया और हार्पर ने अपने पार्लियामेंट हिल स्थित सरकारी कार्यालय में उनसे 40 मिनट तक विचार विमर्श किया।

चार सदस्यों के इस प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका रवाना होने से पहले ओटावा, वेंकवूर तथा केलगरी में बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। इन लोगों ने चीन सरकार का वह आरोप दोहराया कि दलाई लामा

तिब्बत को चीन से अलग करने के प्रयास में हैं। दलाई लामा इस आरोप का हमेशा ही खंडन करते रहते हैं। दलाई लामा का कहना है कि वे तिब्बत के लिये स्वायत्तता चाहते हैं लेकिन चीन प्रायोजित इस प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि यह तो महज अलगाव के लिये दो चरणों वाली प्रक्रिया का हिस्सा भर है।

इस प्रतिनिधि मंडल में एक बौद्ध भिक्षु तथा एक चीनी डाक्टर भी शामिल था। टिबेटन एकेडमी आफ सोशल साइंसेज के प्रमुख सिरेन जियाबु ने कहा, ''उन्होंने अलगाव का अपना अंतिम लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा है।'' क्यूबेक को 1980 तथा 1995 में मिले जनमत संग्रह के अधिकार का जिक्र करते हुए जब इस प्रतिनिधि मंडल से पूछा गया कि क्या चीन सरकार तिब्बतियों को भी इस तरह का मौका देने को तैयार है तो उनका गोलमोल जवाब था, ''यह तो महज रणनीति में बदलाव है।'' लेकिन इस तरह के जवाब देते समय कनाडा के दौरे पर आये इस चीनी प्रतिनिधि मंडल के चेहरों पर चिंता स्पष्ट नजर आ रही थी। उन्होंने एक दूसरे को नोट दिये और सवालों का जवाब देने से बचते रहे।

क्यूबेक की तुलना सबसे पहले एन ने की थी। लेकिन जब एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा तो उसका जवाब था कि, ''दोनों स्थितियों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि कनाडा का इतिहास महज 100 साल पुराना है जबकि चीन 5,000 साल पुराना है।''

जब उनसे फिर पूछा गया कि क्या तिब्बतियों को चीन से अलग होने के बारे में जनमत का विकल्प देना अच्छा विचार है? तो सिरेन ने कहा,''हम तिब्बती लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि तिब्बती लोग जनमत करेंगे।''

इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा का आयोजन चाइना इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन ने किया। इसके बारे में उनका कहना था कि यह एक नागरिक संगठन है जिसका चीन सरकार से कोई संबंध नहीं।

यूरोपीय सांसदों ने 'टीम–टिबेट' का समर्थन किया

ब्रसेल्स, आठ नवंबर यूरोपीय संसद के तिब्बत समर्थक संसदीय मंच टिबेट इंटरग्रुप तथा तिब्बत पर यूरोपीय सांसदों के सम्मेलन के प्रतिभागियों ने तिब्बत की ओलंपिक टीम 'टीम–टिबेट' के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को भेजे एक प्रस्ताव में तिब्बती ६ ाावकों को ओलंपिक खेलों में शामिल करने की अनुमति देने की अपील की। टीम टिबेट के सदस्यों ने यूरोपीय सांसद सम्मेलन में विचार रखे और इस सम्मेलन में शामिल सांसदों से समर्थन मांगा ताकि उनका सपना पूरा हो सके।

टीम टिबेट के समन्वयक केलसंग गोपे ने इस पहल का परिचय दिया और इस दिशा में हुई प्रगति तथा गतिविधियों के बारे में बताया। इन लोगों ने 'तिब्बत को 2008 ओलंपिक में शामिल करो' बैनर के तहत दुनिया भर के तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों के साथ मिलकर मई 2007 से एक अभियान शुरू किया है जिसकी मांग बीजिंग में अगले साल हो रहे ओलंपिक खेलों में टीम टिबेट को शामिल करना है।

टेबल टेनिस के पेमा योको, फुटबाल के धोंदुप गेलेक, टेबल टेनिस के डोमिनिक केलसंग एर्न ने कहा कि ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में अन्य धावकों के साथ चलना उनका सपना है।

टीम टिबेट के सदस्यों की संख्या फिलहाल 30 से अधिक है। तिब्बत नेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष वांगपो टेथांग ने सम्मेलन के समक्ष कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों के मूल सिद्धांतों के प्रति गंभीर है जो उसे तिब्बतियों को ओलंपिक खेलों में शामिल होने के अधिकार को नकारना नहीं चाहिए।

पैनल चर्चा में आईओसी के सदस्य पाल श्मिट ने टीम तिब्बत की दावेदारी को लेकर कुछ चिंताएं जताईं और ओलंपिक चार्ट की शर्तों नियमों का जिक्र किया। लेकिन उन्होंने टीम तिब्बत के खेलों में शामिल होने की संभावना को खारिज नहीं किया।

चार शीतकालीन ओलंपिक में भाग ले चुके एवं फिलहाल यूरोपीय संसद के सदस्य पीटी स्टेस्टनी ने टीम तिब्बत के सदस्यों का हौसला बढ़ाया तथा अपने अनुभवों को उनके साथ बांटा। उन्होंने कहा, ''अगर परिस्थिति की मांग हो तो नियमों में बदलाव किया जा सकता है। ओलंपिक चार्टर में भी कई बार बदलाव हो चुका है।''

ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता डीटर बुमान ने भी टीम तिब्बत के सदस्यों से विचार विमर्श किया और उन्हें जर्मनी में उनके साथ दौड़ में शामिल होने का न्योता दिया। सम्मेलन के पहले दिन के समापन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें टीम टिबेट को ओलंपिक खेल 2008 में भाग लेने की अनुमति का आह्वान किया गया है।

यूरोपीय संसद के तिब्बत समर्थक संसदीय मंच टिबेट इंटरग्रुप तथा तिब्बत पर यूरोपीय सांसदों के सम्मेलन के प्रतिभागियों ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को भेजे एक प्रस्ताव में तिब्बती खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में शामिल करने की अनुमति देने की अपील की। चार शीतकालीन ओलंपिक में भाग ले चुके यूरोपीय सांसद पीटी स्टेस्टनी ने कहा, ''अगर परिस्थिति की मांग हो तो नियमों में बदलाव किया जा सकता है। ओलंपिक चार्टर में भी कई बार बदलाव हो चुका है।''

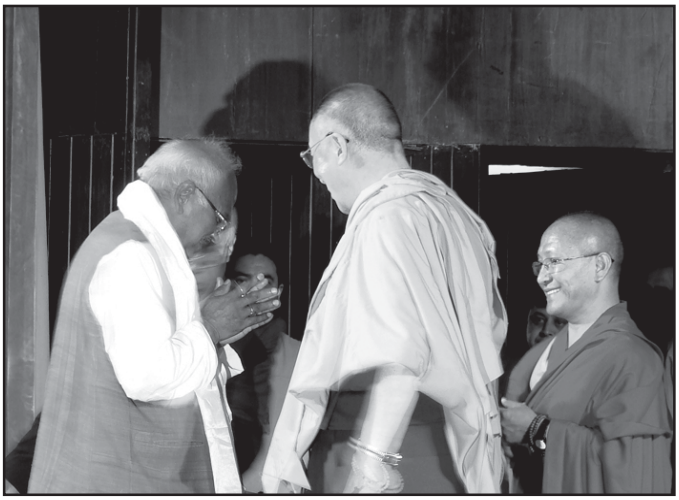

तिब्बत और दलाई लामा पर भारत की जर

अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'कांग्रेशनल गोल्ड मैडल' से सम्मानित हो उनके नागरिक सम्मान समारोह में भाग लिया। 3 नवंबर के दिन इस समारोह का इस समारोह का आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान, भारत में तिब्बत समर्थक सर्वदली ग्रुप फॉर तिबेतन कॉज़' ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व प्रधान वरिष्ठ सांस्कृतिक हस्तियों और वरिष्ठ पूर्व राजनयिकों ने दलाई लामा जी को फूल सरकार के नखरों के आगे बार–बार माथा टेकने वाली भारत सरकार ने एक विशे भारत की चीन नीति के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे इस समारोह में भाग न लें। 'शर्मनाक' कदम बताया। तिब्बत समर्थक संगठनों ने यह कहते हुए दुख व्यक्त कि के आत्सम्मान को चोट पहुंचाई है और दुनिया को दिखाया है कि चीन सरकार के चुकी है। लेकिन सौभाग्य से हैबिटैट सेंटर के सबसे बड़े और दुमंजिला हाल की आरती मेहरा ने सरकार को संदेश भेज दिया कि तिब्बत के सवाल पर सरकार अ

♦ आंखों देखी

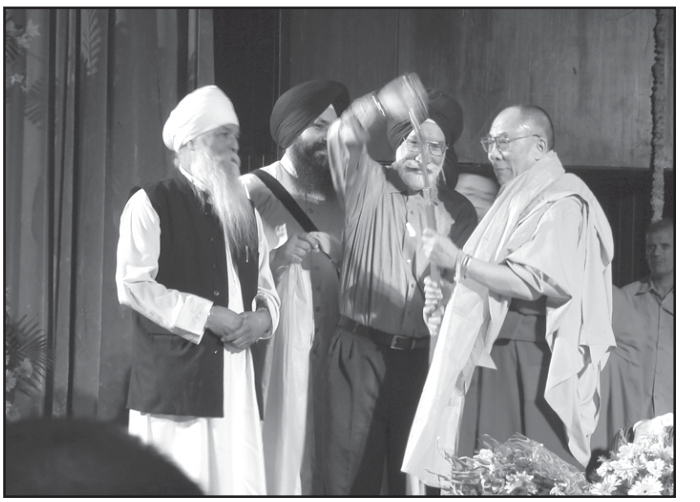

नता और सरकार की राय अलग–अलग है

ने के बाद दलाई लामा जी के भारत लौटने पर भारत के सभी धर्म प्रतिनिधियों ने
आयोजन नई दिल्ली के इंडियन हैबिटैट सेंटर के मुख्य सभागार में किया गया।
य संसदीय मंच और भारत में तिब्बत समर्थक संगठनों के केंद्रीय संगठन 'कोर
नमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने की और समारोह में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों, कई
ल और अपने धार्मिक प्रतीक भेंट करके बधाई और शुभकामनाएं दीं। लेकिन चीन
ष सर्कुलर जारी करके अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बताया कि यह समारोह
सरकार के इस कदम को समाचार पत्रों और कूटनीतिक टिप्पणीकारों ने एक
या कि ऐसा सर्कुलर जारी करने वाले सरकारी अधिकारियों और नेताओं ने भारत
मुकाबले भारत सरकार किस हद तक नीति–विहीन और आत्मविश्वास विहीन हो
भरी हुई सीटों और सीढ़ियों में बैठी दिल्ली की जनता और दिल्ली की मेयर सुश्री
और जनता की राय अलग है। – टिप्पणी और सभी फोटो : **विजय क्रान्ति**

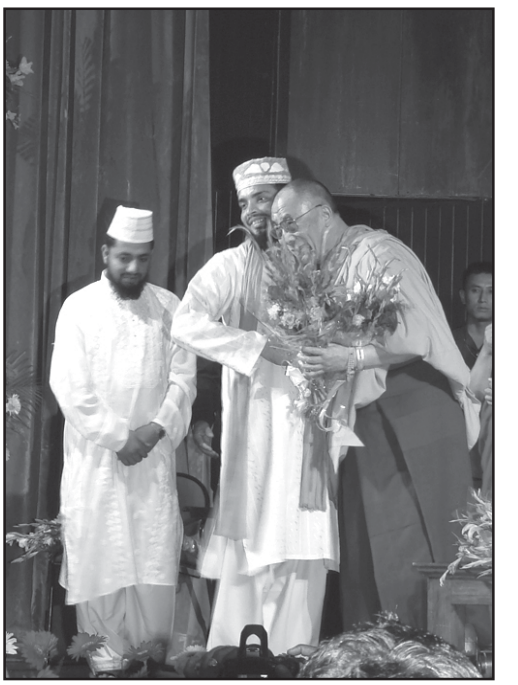

बीजिंग के एक पुल पर तिब्बत समर्थक प्रदर्शन : उपनिवेशवाद के पाप

ओलंपिक प्रदर्शनों को कुचलने के लिए चीन का खुफिया अभियान जोरों पर

चीनी और विदेशी संगठनों पर जानकारियां जुटाने का अभियान चला रही हैं खुफिया एजेंसियां

चीनी खुफिया एजेंसियां चीन की धार्मिक पाबंदियों का विरोध करने वाले ईसाई संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा दारफुर, नरसंहार में चीनी भूमिका का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं। और लोकतंत्र समर्थक संगठनों पर सूचनाएं इकट्ठा कर रही हैं।

एपी, बीजिंग चीन की खुफिया एजेंसियां अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारियों में जुट गई हैं। वे उन विदेशी लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं जो इस आयोजन के दौरान प्रदर्शन कर रंग में भंग डालने की कोशिश कर सकते हैं।

सरकारी एजेंसियां तथा थिंकटेंक उन संभावित विदेशी संगठनों की सूची बनाने में लगे हुए हैं जिनके बारे में आशंका है कि वे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यह जानकारी एक सुरक्षा विशेषज्ञ तथा इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारी ने दी है।

उसने कहा कि एजेंसियां मानवाधिकार संगठनों से भी परे सोच रही हैं। इनमें चीन की धार्मिक पाबंदियों को कम करने की मांग करने वाले ईसाई कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता तथा दारफुर, सूडान में संघर्ष समाप्ति की मांग कर रहे कार्यकर्ता और लोकतंत्र समर्थक संगठन शामिल हैं। सरकारी एजेंसियां इस पहल के तहत विशेषकर गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ सूचनाएं एकत्रित कर रही हैं। इससे पहले अपने देशों पर चीनी शासन का विरोध कर रहे तिब्बती, सिंकियांग के उइगुर और मंगोल, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भड़के हुए चीनी किसान तथा फालुन गोंग अभियान के कार्यकर्ता ही इस तरह की श्रेणी में गिने जाते रहे हैं।

इस सारी कोशिश का उद्देश्य ओलंपिक खेलों के दौरान किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को टालना है। इस अधिकारी ने कहा, ''सभी तरह के प्रदर्शन चिंता का विषय हैं जिनमें अमेरिका विरोधी प्रदर्शन भी शामिल हैं।''

अधिकारी ने कहा कि सरकार यह सूचनाएं जुटाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह के गैर सरकारी संगठन, एनजीओ बाहर से आयेंगे और उनकी योजनाएं क्या हैं। किसी भी बड़े आयोजन से पहले विदेशी सरकारें संभावित विद्रोही संगठनों पर निगरानी तो करती हैं लेकिन चीन ने इस मामले में कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए उन संगठनों को भी निशाना बनाया है जिनकी गतिविधियां अधिकतर देशों में कानूनी मानी जाती हैं। कम्युनिस्ट सरकार वीजा को भी नियंत्रित कर रही है और भीतरी विद्रोह को दबाने के लिये नई नीतियां बना रही है।

ओगिल्वी पब्लिक रिलेशंस वर्ल्डवाइड के चीनी परिचालन के अध्यक्ष स्काट रोनिक ने कहा कि बीजिंग ओलंपिक आयोजन समिति के एक सदस्य के समक्ष उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ संभावित व्यवहार को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। रोनिक के अनुसार उन्होंने उक्त अधिकारी से कहा ''आपको तो इस बात की चिंता करनी है कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी और आप कैसी कार्रवाई करेंगे।''

कई घरेलू खुफिया एजेंसियों का परिचालन करने वाले राष्ट्रीय पुलिस मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बीजिंग ओलंपिक समिति ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा जबकि सुरक्षा विभाग के फोन नंबर प्रकाशित ही नहीं किये गये हैं।

ओलंपिक खेलों के दौरान जोखिम प्रबंधन से जुड़ा एक संस्थान बेरोजगार श्रमिकों में अशांति पर विचार कर रहा है। गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ को लेकर चीन सरकार लंबे समय से चिंतित रही है और उसकी मान्यता है कि ये संगठन विदेशी सरकारों के एजेंटों की तरह काम कर रहे हैं। अनेक संगठन श्रम अधिकारों सहित कई मुद्दों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

दारफुर के लिये अभियान करने वाले कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ने वहां संघर्ष समाप्ति के लिये प्रयास नहीं किये तो वे इस ओलंपिक को 'नरसंहार ओलंपिक' के रूप में प्रचारित करेंगे।

एक सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि जहां तक चीन का विचार है, एनजीओ अस्थिरताकारी संगठन हैं। चीनी नेताओं को नहीं लगता कि किसी तरह का बहिष्कार होगा लेकिन विरोध प्रदर्शन रंग में भंग तो

डाल ही सकता है जिससे आलोचकों को चीन की कम्युनिस्ट सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल जायेगा।

अप्रैल में तिब्बत की आजादी का समर्थन करने वाले चार अमेरिकी नागरिकों ने माउंट एवरेस्ट के आधार शिविर पर तिब्बत की आजादी संबंधी बैनर लहराया था। इसके बाद से विदेशी नागरिकों का तिब्बत जाना और कड़ा एवं सीमित कर दिया गया है। चीन सरकार ने विदेशों में अपने राजदूतों से चीन सरकार विरोधी संगठनों की सूचनाएं भी मांगी हैं।

ओलंपिक के दौरान प्रदर्शन करने वालों को चीन की चेतावनी

बीजिंग से ब्रिटिश समाचार पत्र गार्जियन के संवाददाता जोनाथन वाट्स ने दो नवंबर को समाचार भेजा जिसमें कहा गया है कि चीन ने चेतावनी दी है की अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान किसी भी तरह के अनाधिकृत विरोध को सहन नहीं किया जायेगा। चीन की इस चेतावनी से नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं तथा धार्मिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। यह आयोजन लगभग दो सप्ताह चलेगा।

चीन की चेतावनी उस समय आई है जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 2008 बीजिंग खेलों के बारे में ओलंपिक संधि प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तिब्बत की आजादी के लिये काम कर रहे कार्यकर्ता इस संधि का विरोध कर रहे थे। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का आह्वान किया गया है कि वे अगले साल अगस्त में होने वाले खेलों के दौरान शांति बनायें और इसे बढ़ावा दें।

माउंट एवरेस्ट पर चीन ने मोबाइल फोन सेवा स्टेशन का परीक्षण किया

बीजिंग से एसोसिएटिड प्रेस के अनुसार चीन की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी चायना मोबाइल ने माउंट एवरेस्ट पर ट्रांसमिशन स्टेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

एपी ने चीन की सरकारी संवाद समिति सिन्हुआ का हवाला देते हुए बताया है कि अगले साल ओलंपिक मशाल रैली के दौरान इस क्षेत्र से फोन काल की जा सकेंगी। 21,325 फुट की उंचाई पर इस स्टेशन को स्थापित करने के दौरान उपकरणों की ढुलाई के लिये कंपनी चाइना मोबाइल को याक तथा तिब्बती कुलियों की मदद लेनी पड़ी।

फीफी के एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल मैच में टीम–तिब्बत : बुलंद हौसले

पर्वतारोहरण की शारीरिक दिक्कतों के साथ साथ मशाल को इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि वह खराब मौसम, कम दबाव तथा उंचाई पर भी जलती रह सके। सिन्हुआ ने कहा कि चाइना मोबाइल की इस पहल का उद्देश्य माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के पूरे रास्ते में मोबाइल कनेक्टिविटी मुहैया कराना है। माउंट एवरेस्ट नेपाल तथा चीन के कब्जे वाले तिब्बत की सीमा पर है। चाइना मोबाइल ने दो और स्टेशन स्थापित किये हैं जो 17,060 फुट तथा 10,095 फुट की उंचाई पर हैं। यह पता नहीं चल पाया कि ये दूसरे स्टेशन भी निरंतर काम करेंगे या नहीं।

परीक्षण के तुरंत बाद ही कर्मचारियों ने इस स्टेशन को सर्दियों के लिये पैक कर दिया। इसे अगली गर्मियों में ओलंपिक मशाल के दौरान फिर से शुरू कर दिया जायेगा। मशाल को एवरेस्ट के 29,035 फुट के शिखर तक ले जाने की योजना है।

सिन्हुआ ने कंपनी के अज्ञात प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि मंगलवार की दोपहर को एक कर्मचारी ने चाइना मोबाइल के महाप्रबंधक वेंग चियानचोउ को काल की। प्रवक्ता ने कहा कि स्टेशन का निर्माण काफी कठिन था क्योंकि वहां पर आक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में सिर्फ 38 प्रतिशत है।

सिन्हुआ के अनुसार कंपनी की अनुषंगी तिब्बत मोबाइल ने कहा है कि उक्त स्टेशन पर्वतारोहियों तथा विज्ञानियों की आवश्यकताओं की जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है। चीन की माउंट एवरेस्ट पर मशाल ले जाने की योजना की कड़ी आलोचना हो रही है। अनेक संगठनों का कहना है कि चीन तिब्बत पर अपने कब्जे को वैधता प्रदान करने के लिये यह नाटक किया जा रहा है।

चीन ने चेतावनी दी है की अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान किसी भी तरह के अनाधिकृत विरोध को सहन नहीं किया जायेगा। चीन की इस चेतावनी से नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं तथा धार्मिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

दलाई लामा के ईज़े पहुंचने पर स्थानीय असेंबली नेताओं द्वारा स्वागत : सबका मित्र

दलाई लामा जापान के शिंतो मंदिर में

जापान सरकार ने दलाई लामा की यात्रा रद्द करने की चीनी मांग को ठुकराया

चीन सरकार ने जापान पर दबाव डाला था कि वह उन्हें जापान यात्रा की अनुमति न दे। जापान सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया लेकिन उसने आश्वासन दिया कि उसका कोई नेता दलाई लामा की आगवानी नहीं करेगा।

तोक्यो परम पावन दलाई लामा ने 15 से 23 नवंबर के बीच जापान की 9 दिन की यात्रा की। इस दौरान 18 नवंबर को वह वहां के सबसे पवित्र माने जाने वाले शिंतो मंदिर में भी गये और वहां प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी हाल ही की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को लेकर चीन द्वारा की जा रही आलोचनाओं को खारिज कर दिया। मंदिर मे दर्शन के बाद उन्होंने निकटवर्ती कोगाखन यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दिया।

दलाई लामा ने इससे एक दिन पहले 17 तारीख को ईसे में संवाददाताओं को बताया कि उनका मिशन विभिन्न धर्मों में सद्भाव बढ़ाना है। उन्होंने दुनिया भर के धार्मिक नेताओं के बीच विचार विमर्श की बात की। दलाई लामा ने कहा कि अगर उनका निर्वासन में ही निधन हो जाता है तो उनके मिशन को जारी रखने के लिये उनका उत्तराधिकारी चीनी नियंत्रण से बाहर वाले किसी इलाके में नया जन्म लेगा।

उन्होंने फिर दोहराया कि वह तिब्बत की आजादी के लिये नहीं बल्कि स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। जापानी मीडिया के अनुसार दलाई लामा ने चीन के इस आरोप को नकार दिया कि वह 'अलगाववादी' हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान दलाई लामा योकोहामा में एक बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए।

दलाई लामा की यह यात्रा चीन सरकार के भारी विरोध के बावजूद हुई। चीन सरकार ने जापान सरकार पर इस बात का दबाव डाला था कि वह उन्हें जापान यात्रा की अनुमति न दे। जापान सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया लेकिन उसने चीन को यह आश्वासन दिया कि उसका कोई सरकारी नेता दलाई लामा की आगवानी नहीं करेगा। बाद में जापान के खिलाफ चीन सरकार के इस आरोप की दलाई लामा ने आलोचना की कि वह 'अलगाववादी गतिविधियों' के लिये दलाई लामा को अपने यहां आने की अनुमति दे रहा है।

दलाई लामा की विदेश यात्राओं से चीन हमेशा नाराज रहता है और वह इनकी आलोचना भी करता रहता है। उसका कहना है कि दलाई लामा की अगवानी कर विदेशी सरकारें उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रही हैं।

दलाई लामा की जापान यात्रा को लेकर चीन सरकार इसलिए भी परेशान थी कि पिछले कुछ महीनों के दौरान दलाई लामा की कनाडा, जर्मनी तथा अमेरिका यात्राओं के दौरान वहां के शीर्ष नेतृत्व ने दलाई लामा का खुद स्वागत किया था और चीन सरकार के भारी विरोध के बावजूद उनके साथ मुलाकातें की थीं।

रूसी और मंगोलियाई बौद्धों ने दलाई लामा के लिये प्रार्थना की

धर्मशाला, 11 नंवबर धर्मशाला में विशेष बौद्ध त्योहार के समापन अवसर पर रूस तथा मंगोलिया से आए लगभग 700 बौद्धों ने दलाई लामा की दीर्घायु के लिये प्रार्थना विशेष प्रार्थना की। यह पहला मौका थ जब इस विशेष त्योहार के लिए मंगोलिया तथा रूस से इतनी बड़ी संख्या में बौद्ध शामिल हुए।

इसमें शामिल होने के लिये अमेरिका से आई एक रूसी बुद्धिस्ट इरना ने कहा, ''इस तरह के समारोह में हिस्से लेना हमेशा ही एक आशीर्वाद और सम्मान की तरह होता है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है।''

रूस की ही एक अन्य बौद्ध श्रद्धालु पोलिना ने तिब्बती संस्कृति को जीवित रखने के लिये भारत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ''हम यहां आकर बहुत खुश हैं हम सकारात्मक भावनाओं से ओत प्रोत हैं। हम भारतीय लोगों के आभारी हैं कि आपने परम पावन दलाई लामा तथा तिब्बती शरणार्थियों की मदद की है और उन्हें यहां आराम से रहने की आजादी दे रहे हैं।''

अमेरिका में वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने के बाद दलाई लामा का यह पहला सार्वजनिक प्रवचन था जो उन्होंने 9 नवंबर को प्रवचन दिया।

दलाई लामा के दर्शन करने, उनके प्रवचन सुनने, बौद्ध प्रार्थनाओं में भाग लेने तथा तिब्बती संस्कृति को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से हजारों लोग धर्मशाला आ रहे हैं।

रिचर्ड गेअर को तिब्बत तथा एड्स कार्य के लिए लोकोपकार अवार्ड

फिलाडेल्फिया तिब्बत की आजादी तथा एचआईवी एड्स के लिये अपना समय एवं धन देने वाले फिल्मी अदाकार रिचर्ड गेअर को फिलाडेल्फिया शहर का प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार 'मेरियल एंडरसन अवार्ड' दिया गया।

इस अवार्ड की स्थापना 1930 के दशक में अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने वाली अश्वेत अमेरिकी ओपेरा गायिका के नाम पर की गई है। एंडरसन ने 1939 में व्हाइट हाउस में अपनी कला का प्रदर्शन किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली अश्वेत महिला थीं। उन्हों 1963 में 'मेडल आफ फ्रीडम' प्रदान किया गया था।

किमेल सेंटर फार द परफार्मिंग आर्ट्स में आयोजित भव्य समारोह में गेअर को अवार्ड तथा 1,00,000 अमेरिकी डालर की राशि प्रदान की गई।

इस अवसर पर गेअर ने कहा कि यह अवार्ड पाकर वे अभिभूत हैं। अभिनेता तथा कार्यकर्ता दोनों की भूमिका निभाने के लिये गेअर की सराहना की गई। उन्होंने अपनी ख्याति तथा पैसे दोनों का इस्तेमाल वैश्विक मुद्दों के लिये किया है।

गेअर एक बौद्ध हैं और वह 1978 से ही तिब्बत की आजादी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयार्क के टिबेट हाउस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके लिए धन भी दिया है। वह तिब्बत के समर्थन में चलने वाले संगठन 'इंटरनेशनल कैंपेन फार टिबेट' के बोर्ड अध्यक्ष भी हैं।

उन्होंने एचआईवी एड्स रोगियों के प्रति जागरुकता के लिये 'हीलिंग द डिवाइड' संगठन की स्थापना की है। वह 'एन आफिसर एंड ए जेंटलमेन', 'प्रैटी वूमेन' तथा 'शिकागो शिकागो' आदि में भूमिका निभा चुके हैं।

ताइवान से शांति वार्ता की चीनी पेशकश

बीजिंग, 15 अक्तूबर चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने ताइवान के साथ अपने वैमनस्य को समाप्त करने के लिये फिर बातचीत करने और चीन की शर्तों पर शांति समझौते की अपील भी की है।

लेकिन कुछ लोगों का मानना है यह सब बीजिंग ओलंपिक तक अच्छी छवि बनाने की एक चीनी कवायद है। चीन के प्रधानमंत्री हू जिंताओ ने कहा, ''हम औपचारिक रूप से कहना चाहेंगे कि हम चीन के एक नीति के सिद्धांत के आधार पर दोनों देशों के बीच वैमनस्य खत्म कर विकास के नये दौर में प्रवेश करने के यिले बातचीत शुरू करने को तैयार हैं।''

एक तिब्बती सम्मेलन में प्रशंसकों के बीच रिचर्ड गेअर : मानवतावादी नज़रिया

हू चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 17वीं नेशनल कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ताइवान की आजादी से जुड़े लोग अलगाव की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। वे आपसी रिश्तों के शांतिपूर्ण विकास को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि चीन किसी भी मुद्दे पर ताइवान के किसी भी राजनीतिक दल के साथ बातचीत करने को तैयार है। हम ताइवान के हितों को पूरा करने, वहां शांति बनाये रखने ओर शांतिपूर्ण तरीके से देश के एकीकरण के लिये हरसंभव उपाय करेंगे।

हू ने इस बात पर भी जोर दिया कि लंबे समय से पार्टी का रुख रहा है कि हम एक चीन सिद्धांत की नीति को नहीं छोड़ेंगे। हम ताइवान की आजादी को लेकर जारी गतिविधियों का विरोध किये जाने के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, ''चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता में कोई विभाजन नहीं होने दिया जायेगा। इस बारे में कोई भी फैसला ताइवान समेत चीनी जनता करेगी।'' हू ने कहा कि हमारी इच्छा दोनों पक्षों के एकीकरण के लिये ईमानदारी के साथ हरसंभव उपाय करने की है। हम किसी को भी अलग ताइवान बनाने की अनुमति नहीं देंगे।

चीन में कम्युनिस्ट सत्तापलट के बाद 1949 में चीन और ताइवान अलग हो गये थे।

रिचर्ड गेअर ने कहा कि यह अवार्ड पाकर वे अभिभूत हैं। अभिनेता तथा कार्यकर्ता दोनों की भूमिका निभाने के लिये गेअर की सराहना की गई। उन्होंने अपनी ख्याति तथा पैसे दोनों का इस्तेमाल वैश्विक मुद्दों के लिये किया है।

समारोह में मंच पर दलाई लामा और श्री इंद्र कुमार गुजराल : शांतिदूत का अभिनंदन

दलाई लामा समारोह पर भारत सरकार के निर्देश की निंदा

दलाई लामा 'भारत–रत्न' से सम्मानित करने योग्य

भारत सरकार ने अपने मंत्रियों को 3 नवंबर के दिन नई दिल्ली में दलाई लामा जी के स्वागत समारोह में भाग लेने से रोकने का आदेश जारी करके अपनी कूटनीतिक नासमझी और राष्ट्रीय आत्मसम्मान की कमी का दुखद परिचय दिया है।

परम पावन दलाई लामा को अमेरिकी संसद की ओर से अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'कांग्रेशनल गोल्ड मैडल' दिए जाने के उपलक्ष्य में 3 नवंबर के दिन नई दिल्ली के इंडिया हैबिटैट सैंटर में दलाई लामा जी का नागरिक अभिनंदन किया गया। इसका आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान, भारत का सर्वदलीय तिब्बत समर्थक संसदीय मंच, तिब्बत समर्थक भारतीय संगठनों के साझा संयोजक मंच 'कोर ग्रुप फॉर तिबेतन कॉज़' और विभिन्न धार्मिक प्रतिनिधियों ने किया।

अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने की और इसमें दिल्ली की मेयर सुश्री आरती मेहरा, संसदीय मंच के नेता श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, पूर्व राजदूत श्री दिलिप मेहता और श्रीमती कपिला वास्यायन जैसी हस्तियों के अलावा सभी प्रमुख धर्मों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। समारोह का आयोजन हैबिटैट सेंटर के मुख्य सभागार में किया गया था। हालांकि यह सभागार वहां का सबसे बड़ा है और इसमें बैठने की दुमंजिली व्यवस्था है। पर इसके बावजूद पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था और सीट न मिलने के कारण सीढ़ियों और गलियारों के सभी खाली स्थानों पर सैंकड़ों लोगों ने खड़े होकर भाग लिया।

परमपावन दलाई लामा के स्वागत में जिन लोगों ने वक्तव्य दिए उनमें श्री गुजराल के अलावा श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव श्री लखन लाल मेहरोत्रा भी थे। सभा का संचालन श्री राजीव मेहरोत्रा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन श्री नंद किशोर त्रिखा ने किया।

लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक जारी किए गए निर्देश के कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता समारोह में भाग नहीं ले पाए। अपने शालीन व्यक्तित्क के कारण अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच भी सम्मान पाने वाली श्रीमती दीक्षित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं और वह इसके लिए अपनी स्वीकृति पहले ही दे चुकी थीं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जानी होने के बाद उन्होंने आयोजकों को संदेश भेजा कि अचानक एक सरकारी काम आने की वजह से उन्हें मुंबई जाना पड़ रहा है।

सरकार के इस निर्णय की व्यापक स्तर पर निंदा हुई और इसे चीन के सामने भारत के राष्ट्रीय अपमान की संज्ञा दी गई। बाद में संसदीय मंच और कोर ग्रुप की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसे यहां पेश किया जा रहा है:

नई दिल्ली–6 नवंबर भारत सरकार ने अपने मंत्रियों को 3 नवंबर के दिन नई दिल्ली में दलाई लामा जी के स्वागत समारोह में भाग लेने से रोकने का आदेश जारी करके अपनी कूटनीतिक नासमझी और राष्ट्रीय आत्मसम्मान की कमी का दुखद परिचय दिया है। इस समारोह का आयोजन दलाई लामा जी को अमेरिकी संसद द्वारा सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान ''कांग्रेशनल गोल्ड मैडल'' दिए जाने के उपलक्ष्य में गांधी शांति प्रतिष्ठान, भारतीय संसद के सर्वदलीय संसदीय मंच और भारत के सभी तिब्बत समर्थक संगठनों के साझा मंच कोर ग्रुप फार तिबेतन कॉज़ ने किया था। अमेरिका में इस पुरस्कार का रुतबा भारत में दिए जाने वाले 'भारत–रत्न' जैसा है।

भारत सरकार का यह निर्णय इन आशंकाओं के संदर्भ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने यह सब उस चीन सरकार को खुश करने के लिए किया है जो एक लंबे समय से लगातार भारत के राष्ट्रीय हितों पर चोट करती आ रही है और भारतीय मानस के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई मौका नहीं चूकती। पिछले दिनों श्रीमती सोनिया गांधी की चीन यात्रा के एक दिन बाद ही अरुणाचल प्रदेश पर अपने अधिकार वाला उसका अशोभनीय बयान उसकी इसी नीति का प्रदर्शन था।

भारत सरकार के इस संवेदनहीन फैसले से न केवल भारत के करोड़ों तिब्बत प्रेमियों और दलाई

लामा जी के समर्थकों को दुख पहुंचा है बल्कि इसने दुनिया भर के उन उन करोड़ों शांतिप्रेमियों को भी आहत किया है जो शांति और सदभाव के रास्ते विश्व की कठिन राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का मार्ग दिखाने वाले दलाई लामा के प्रशंसक हैं।

हमें यह देखकर दुख हुआ है कि भारत सरकार के नीति निर्धारकों ने इतनी सी बात को भी समझने का प्रयास नहीं किया कि इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य कोई राजनीति आंदोलन चलाना नहीं बल्कि दलाई लामा जी के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर विशाल और प्रशंसनीय व्यक्तित्व को रेखांकित करना था। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में रहने वाले दलाई लामा पिछले पचास साल में जिस तरह से शांति, अहिंसा, धार्मिक सद्भाव और विश्व भाइचारे के सबसे बड़े प्रतीक बन कर उभरे हैं वह भारत के लिए भी गौरव की बात है। अमेरिकी संसद की ओर से उन्हें दिया गया यह सम्मान उन कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की कड़ी (50 से अधिक) में है जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार और रेमन मैगसेसे पुरस्कार जैसे सम्मान भी शामिल हैं।

बल्कि हमें यह देखकर दुख होता है कि एक ओर जहां पूरी दुनिया दलाई लामा के युग पुरुष व्यक्तित्व को पहचान कर उन्हें सम्मानित करने की होड़ में लगी हुई है वहीं भारत सरकार अपने यहां रहने वाले इस मेहमान के सम्मान में आयोजित समारोह में अपने मंत्रियों को मुह दिखाने से रोकने के लिए सरकारी आदेश जारी करती है।

हम भारत सरकार को इस मौके पर यह याद दिलाना चाहते हैं कि दलाई लामा चीन सरकार से बातचीत और अहिंसक सुलह के रास्ते तिब्बत की समस्या हल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने यह साहसिक गांधीवादी कदम इस तथ्य के बावजूद उठाया है कि चीन ने उनके देश पर पचास साल से जबरन उपनिवेशवादी कब्जा जमाया हुआ है। और यह भी कि इस दौर में चीनी सेना के अमानुशिक अत्याचारों की वजह से वहां 12 लाख से ज्यादा तिब्बतियों की हत्या की जा चुकी है।

इसलिए उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में हम भारत के सभी न्याय समर्थकों, मानवाधिकार समर्थकों और तिब्बत समर्थको की ओर से भारत सरकार से मांग करते हैं कि:

1. इस तरह के अपरिपक्व कूटनीतिक फैसले करने के बजाए भारत सरकार को चीनी नेताओं के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके उन्हें दलाई लामा जी के साथ बातचीत के रास्ते तिब्बत समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वे चीनी नेताओं को समझाएं कि तिब्बत के अपदस्थ शासक और तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक–सामाजिक नेता होने के कारण दलाई लामा ही तिब्बती जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। इससे भारत को भी अपने पड़ोस में शांति स्थापित करने का लाभ मिलेगा और चीनी नेताओं को भी उस शर्मनाक स्थिति से सम्मानपूर्वक उबरने का मौका मिलेगा जिसमें वे अपनी उपनिवेशवादी करतूतों के कारण फंसे हुए हैं।

2. जिस तरह से यूरोपीय संसद और अमेरिकी संसद की तरह विश्व की कई संसदों नें दलाई लामा जी मार्गदर्शन पाने के लिए उन्हें अपने यहां बुलाया है उसी तरह उन्हें लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संसदीय अधिवेशन में आमंत्रित किया जाना चाहिए।

3. भारत में लगभग पचास साल से रहने वाले दलाई लामा महात्मा गांधी के विचारों और भारतीय विचार दर्शन से प्रेरणा पाकर आज के युग के सबसे सम्मानित शांतिदूत के रूप में दुनिया में सम्मानित किए जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक हो चुका है कि भारत के इस सपूत को 'भारत–रत्न' से सम्मानित करने का फैसला किया जाए जिसे वास्तव में कई साल पहले ले लिया जाना चाहिए था।

– विजय क्रान्ति

सभा को संबोधित करते हुए सांसद श्री बशिष्ठ नारायण सिंह : युग पुरुष का सम्मान

भारत में लगभग पचास साल से रहने वाले दलाई लामा महात्मा गांधी के विचारों और भारतीय विचार दर्शन से प्रेरणा पाकर आज के युग के सबसे सम्मानित शांतिदूत के रूप में दुनिया में सम्मानित किए जा रहे हैं। इसलिए भारत के इस सपूत को 'भारत–रत्न' से सम्मानित करने का फैसला किया जाए जिसे वास्तव में कई साल पहले ले लिया जाना चाहिए था।

''अनीति की नीति''

हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय, 6 नवंबर

जब 'दुनिया की छत' की बात आती है तो भारत की नीति टाइमलेस लगती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में दलाई लामा के सम्मान समारोह

दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए डा. नंद किशोर त्रिखा : जनता की ओर से

से दूर रहने को कहा। यहां तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी समारोह में शामिल होने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरी नहीं उतरीं। वे यह कहते हुए निकल गईं कि उन्हें मुंबई जाने की जल्दी है जबकि रपटें है कि उन्होंने समारोह में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। यह बिलकुल अप्रत्याशित तो नहीं है क्योंकि भारत चीन के साथ किसी तरह का राजनयिक युद्ध नहीं छेड़ना चाहता इसलिए इस तरह के समारोहों से बच रहा है।

तिब्बत को लेकर चीन इतना अधिक संवेदनशील है कि भारत हमेशा ही दलाई लामा से एक निश्चित दूरी बनाकर चलता है। चीन का आरोप है कि दलाई लामा तिब्बत की आजादी के लिये अभियान चला रहे हैं। यह अलग बात है कि 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद से ही निर्वासित जीवन जी रहे इस धार्मिक नेता ने अब तिब्बत की पूरी आजादी के बजाए केवल व्यापक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री समदोंग रिंपोछे भी तिब्बत–चीन वार्ताओं के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए दुनिया भर के तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थक संगठनों से आग्रह करते आ रहे हैं कि वे विदेश यात्रा पर आने वाले चीनी अधिकारियों और नेताओं के विरोध ा में प्रदर्शन करना रोक दें।

यह एक खुला हुआ रहस्य है कि तिब्बत पर चीन के निरंकुश दमन ने अनुमानतः 14 लाख तिब्बतियों की जिंदगी छीन ली है। चीन अपने हान समुदाय को तिब्बत में बसने को आकर्षित करता रहता है ताकि मूल तिब्बती लोगों को अल्पसंख्यक किया जा सके।

गत पचास साल के भारत–चीन संबंध दिखाते हैं कि भारत किस तरह से चीन की वास्तविक नीतियों के फेर में आता है। चीन के साथ संभावित तनाव को टालने के लिये भारतीय नीतिकार तिब्बती मुद्दे को हाशिये पर कर रहे हैं।

दूसरी ओर चीन की नीतियां दर्शाती हैं कि उनके लिये भारत के साथ साथ तिब्बत भी केंद्रीय मुद्दा है। तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग बनाने से चीन के पास भारतीय भूभाग पर दावा करने के लिये अधिक जगह होगी। सवाल तो यही है कि क्या भारत को अपनी नीति में संशोधन की राजनीतिक इच्छाशक्ति मिलेगी?

''दलाई लामा का सम्मान समारोह भारतीय नीति के अनुरूप नहीं'' विदेश सचिव

एएनआई में स्मिता प्रकाश की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 11 नवंबर भारत के विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने 11 नवंबर को कहा कि तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के सम्मान के लिये पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित समारोह भारत सरकार की तिब्बत नीति के अनुकूल नहीं था। इसी कारण सरकार ने अपने मंत्रियों को इस आयोजन से दूर रहने के बारे में परिपत्र जारी किया था।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ रूस की यात्रा पर जा रहे श्री मेनन ने कहा, ''अगर कोई व्यक्ति ऐसा समारोह आयोजित करता है जो तिब्बत पर भारत की नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो भारत सरकार के प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं ले सकते। परिपत्र जारी करने के पीछे यही तर्क था।''

भारत ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन के अंग के रूप में स्वीकार किया हुआ है। मेनन ने जिस समारोह संबंधी सवाल का जवाब दिया उसका आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा आल इंडिया पार्लियामेंटरी फोरम फार तिब्बत ने किया था। उन्होंने कहा कि दलाई लामा एक मान्य धार्मिक हस्ती हैं जिन्होंने यह कहा है कि वे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और अपने इस वादे पर वे पांच दशक लंबे प्रवास के दौरान पूरी तरह से अडिग रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''दलाई लामा के प्रति हमारा सम्मान कायम है।'' परम पावन दलाई लामा को अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान कांग्रेशनल मेडल से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से चीन और अमेरिका में वाकयुद्ध शुरू हो गया है। चीन दलाई लामा को एक धार्मिक नेता से अधिक एक विद्रोही मानता है। वहीं अमेरिका ने चीन से आग्रह किया है कि वह तिब्बत के मुद्दे को सुलझाने के लिये दलाई लामा से बातचीत करे।

श्री मेनन ने कहा, ''अगर कोई व्यक्ति ऐसा समारोह आयोजित करता है जो तिब्बत पर भारत की नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो भारत सरकार के प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं ले सकते। परिपत्र जारी करने के पीछे यही तर्क था।'' पर उन्होंने यह भी कहा कि ''दलाई लामा के प्रति हमारा सम्मान कायम है।''